आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 25.10.2025
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार में एआई और कृत्रिम सामग्री के दुरुपयोग से बचने को कहा।

- उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती उत्सव की तैयारियां जोरों पर। पहली से 10 नवंबर तक प्रदेशभर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

- प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान युद्धस्तर पर जारी। 98 प्रतिशत कार्य पूरा।

- हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने हरिद्वार–नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।

निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और प्रचार प्रतिनिधियों से चुनाव के दौरान कृत्रिम रूप से और एआई–जनित सामग्री का ज़िम्मेदारी से उपयोग करने का आग्रह किया है।

राज्य स्थापना रजत जंयती

उत्तराखंड में इस साल राज्य स्थापना दिवस को विशेष रूप से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर इसे रजत जयंती दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अपर सचिव, बंशीधर तिवारी ने बताया कि इसके तहत पहली नवंबर से 10 नवंबर तक प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान विधानसभा का एक विशेष सत्र भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य के विकास के रोडमैप और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी।

कैबिनेट मंत्री समीक्षा

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में जल संस्थान व जल निगम के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मसूरी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल व संबंधित विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए पेयजल से संबंधित सभी विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने युमना पेयजल पंम्पिग योजना के माध्यम से मसूरी शहर में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। श्री जोशी ने कहा कि सरकार, आमजन की मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है और पेयजल जैसी आवश्यक सेवा में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पेंशन योजना

सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली– एनपीएस और एकीकृत पेंशन योजना– यूपीएस दोनों के तहत एलसी–75 और बीएलसी जैसे निवेश विकल्पों के विस्तार को मंजूरी दे दी है। यह कदम उन कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग के अनुरूप है, जो चाहते थे कि उन्हें भी निजी क्षेत्र की तरह निवेश के अधिक लचीले विकल्प मिलें।

गड्ढा मुक्त सड़कें

प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान युद्धस्तर पर जारी है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि प्रदेश के मुख्य मार्गों को गड्ढा मुक्त करने का लगभग 98 प्रतिशत काम लगभग पूरा हो चुका है, और बचा हुआ कार्य भी शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी जिले में बीआरओ और हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ हिस्से का कार्य शेष हैं, जिन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे ज्यादा यातायात वाली ग्रामीण सड़कों की मरम्मत को भी प्राथमिकता दें। श्री पांडे ने बताया कि सरकार द्वारा दी गई समय सीमा 31 अक्टूबर से पहले ही प्रदेश के सभी मुख्य मार्गो को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा।

जिलाधिकारी निरीक्षण

हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज हरिद्वार–नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्य की गुणवत्ता, प्रगति, सुरक्षा मानकों और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का विस्तार से जायज़ा लिया। जिलाधिकारी ने रसियाबगढ़ के पास बने लगभग दो किलोमीटर डायवर्जन मार्ग का रिपेयरिंग कार्य आज ही तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिये। इसके अलावा मार्ग रिपेयरिंग कार्य तीन दिन के भीतर पूरा करने और प्रगति रिपोर्ट फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परियोजना निदेशक एस. शर्मा ने बताया कि तीन दिन के भीतर डायवर्जन का रिपेयरिंग कार्य पूरा कर लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि नजीबाबाद बायपास निर्माण कार्य भी इस वर्ष के अन्त तक पूरा कर लिया जायेगा। इससे हरिद्वार आने वाले यात्रियों को नजीबाबाद शहर में लगने वाले जाम और धीमे ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी तथा यात्रियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

जीएसटी बचत उत्सव

वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 सितंबर को इसकी शुरूआत की थी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आवास क्षेत्र में नई जीएसटी दरें नागरिकों के लिए मददगार साबित हो रही हैं।

उप कारागार निरीक्षण

नैनीताल के जिला जज हरीश गोयल, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद मीणा ने हल्द्वानी उपकारागार का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही कुछ बंदियों से भी बातचीत कर उनके रहन–सहन और सुविधाओं की जानकारी ली।